

# फायर टैक्स ले सकती है मप्र सरकार

अग्रिशनम सेवाओं को बेहतर करने का प्रयास

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 4 जून. दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड ने देश के साथ ही प्रदेश सरकार को भी हिलाकर रख दिया है. लिहाजा अब प्रदेश के लिए प्रस्तावित मप्र अग्रिशनम एवं आपातकाली सेवाएं विधेयक-2026 को लेकर एक बार फिर गुरुवार को मंथन किया गया. इस दौरान गंभीरता से विचार किया गया कि यदि प्रदेश में अग्रिशनम सेवाओं को बेहतर करना है तो उसके लिए फायर टैक्स लेना होगा, यानी नए विधेयक में इस मौसदे को भी शामिल किया जा सकता है.

वहीं नए एक्ट में फायर सेफ्टी ऑफिसर और अन्य तकनीकी

दिल्ली अग्निकांड के बाद प्रदेश में नए फायर एक्ट पर फिर मंथन



व्यक्तियों को शैक्षणिक योग्यता व अनुभव का स्पष्ट निर्धारण किया जाएगा, जिससे कि तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्ति ही सेवारत हों. इसी क्रम में अब दूसरे राज्यों के नियमों का भी अध्ययन करने को तैयारी कर ली गई है. यहां बता दें कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश के नए फायर एक्ट का मसौदा लगभग तैयार कर लिया था और उसे अंतिम रूप भी दे दिया था,

भारत सरकार के मॉडल एक्ट के अनुरूप हों नियम

मंत्री विजयवर्गीय ने निर्देश दिए कि मप्र अग्रिशनम एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 में भारत सरकार के मॉडल एक्ट के नियमों के अनुसार परिवर्तन किए जाएं. उन्होंने कहा कि भविष्य में मध्यप्रदेश में बड़ी इमारतें, इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज आएंगी, जिसके अनुरूप हमारे पास अत्याधुनिक उपकरण, बेहतर तकनीक और प्रशिक्षित मानव संसाधन होना चाहिए, जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति में विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सके.

लेकिन दिल्ली की घटना के बाद नए सिरे से इसमें और नए संशोधनों को शामिल किया जाएगा. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को मंत्रालय में इस संबंध में आला अफसरों को तलब किया और नए प्रस्तावित एक्ट की समीक्षा की. बैठक में मप्र कॉलोनी अधिनियम 2026 के प्रावधानों को लेकर भी समीक्षा की गई. बैठक में मंत्री विजयवर्गीय ने निर्देश दिए कि सभी बिल्डिंगों में

एम्जिट प्लान और पाइपलाइन का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए. बैठक में अग्रिशनम सेवाओं को बेहतर करने के लिए फायर टैक्स लेने के सुझाव पर भी गंभीरता से चर्चा की गई. दोनों ही एक्ट को लेकर हुए सुझावों के आधार पर जरूरी संशोधन किए जाएंगे और फिर अगले सप्ताह इन दोनों ही एक्ट को मंत्री के सामने पेश किया जाएगा.

विजयवर्गीय ने वर्तमान में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में उपलब्ध फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड और कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधन के लिए विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाई जाए, जिससे अमला किसी भी आपात स्थिति में कार्य करने में पूरी तरह सक्षम हो. बैठक में मप्र कॉलोनी अधिनियम 2026 के प्रस्तावित प्रारूप का प्रजेंटेशन भी किया गया. इसमें कॉलोनी निजस्ट्रीकरण, विकास अनुज्ञा, रियल्टी के उल्लंघन और अनधिकृत, अविकसित व अवैध कॉलोनीयों में कार्रवाई से जुड़े नियमों पर चर्चा की गई.

तापमान कम लेकिन उमस कर रही परेशान

इंदौर. गुरुवार को इंदौर में मौसम साफ रहा और तापमान भी सामान्य हो रहा, लेकिन दो दिन के आंधी तूफान के बाद आज शहर में उमस से आमजन हलाकान होते रहे. आज शहर का तापमान 38.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम है, मगर शाम छह बजे भी 38 डिग्री तापमान बना हुआ था. इससे शाम को गर्मी और उमस से राहत नहीं मिली. वहीं रात का तापमान भी 3 डिग्री बढ़कर कल रात के तापमान 22.4 डिग्री से ज्यादा रहा. चूं भले ही रात का पारा सामान्य माना जाए, लेकिन रात को उमस से क्लर, एसी बिना राहत नहीं मिली. आज शहर में दिन में 17 से 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है. मौसम विभाग का अनुमान है कि आज और कल मानसून पूर्व की हल्की बारिश हो सकती है.

कार दुर्घटनाग्रस्त, विधायक योगेंद्र सिंह को पहुंची चोट

सिवनी. जिले में लखनादीन से कांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह बाबा गुरुवार को एक सड़क दुर्घटना में मामूली रूप से घायल हो गए. धूमा थाना क्षेत्र में उनकी स्कॉर्पियो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई. प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक अपने वाहन से यात्रा कर रहे थे. इसी दौरान धूमा क्षेत्र में बंजारी हाई स्कूल के सामने अचानक सड़क पर एक गाय आ गई. गाय को बचाने के प्रयास में चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और स्कॉर्पियो हाई स्कूल की बाउंड्री वॉल से टकरा गई. दुर्घटना के बाद वाहन में आग लग गई. हालांकि आग फैलने से पहले विधायक, उनका गनमैन, निजी सहायक और चालक वाहन से बाहर निकल आए, जिससे बड़ा अग्निच्छल टल गया. दुर्घटना में विधायक को मामूली चोटें आई हैं, जबकि वाहन में सवार अन्य सभी लोग सुरक्षित बताए गए हैं.

## चुनाव में वोटों के नाम जोड़ने ऑनलाइन सुविधा

स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां प्रारंभ

8317 आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किया



प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 4 जून. प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को नाम जोड़ने, कटवाने और नाम संशोधन के लिये ऑनलाइन सुविधा दी गयी है. इस सुविधा का लाभ लेते हुए कुल 8317 आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किया. इनमें से नगरीय निकायों में 1496 और पंचायतों में 6848 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए.

राज्य निर्वाचन आयोग मनोज श्रीवास्तव के मुताबिक नगरीय निकायों में 675 ऑनलाइन आवेदन नाम जोड़ने, 770 नाम कटवाने और 24 आवेदन नाम में संशोधन के लिये प्राप्त हुए हैं. वहीं त्रि-स्तरीय पंचायतों में 1701 आवेदन नाम जुड़वाने, 4960 नाम कटवाने और 187 आवेदन नाम में संशोधन के लिये प्राप्त हुए हैं. इन सभी आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है.

## आम जनता तक नहीं पहुंच रहा विकास का लाभ

विशेष संवाददाता भोपाल, 4 जून. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रतलाम में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए देश में बढ़ती आर्थिक असमानता और सामाजिक विषमता को लेकर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि देश की बढ़ी संपत्ति सीमित लोगों के हाथों में सिमटती जा रही है, जिससे आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है.

जीतू पटवारी ने कहा कि देश की संपदा का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा लोगों के नियंत्रण में पहुंच गया है, जबकि किसान, मजदूर



और मध्यम वर्ग आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि विकास और आर्थिक प्रगति का लाभ आम नागरिकों तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है. उन्होंने पूर्व के आर्थिक संकटों का उल्लेख करते हुए कहा कि समृद्धि, रोजगार सृजन और

मुख्यमंत्री द्वारा हाल में उनके खिलाफ की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए पटवारी ने इसे लोकतांत्रिक राजनीतिक संवाद की गरिमा के अनुरूप नहीं बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की भाषा से विशेष मीडिया पर वैमनस्य को बढ़ावा मिला है और राजनीतिक विरोधी विभाजनकारी राजनीति को प्रोत्साहित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक सद्भाव और समावेशी राजनीति के प्रति प्रतिबद्ध है. जनता वस्तुविक मुद्दों पर जवाब चाहती है और लोकतांत्रिक माध्यमों से अपना फैसला सुनाएगी.

महंगाई से राहत के दावों के बावजूद देश के अनेक वर्ग आज भी कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं. उनके अनुसार संपत्ति का लगातार सीमित हाथों में केंद्रित होना चिंता का विषय है. कांग्रेस नेता ने वर्षों से बार-बार दिए जा रहे 'देश को बचाने' जैसे नारों पर भी सवाल उठाते हुए

कहा कि यदि देश निरंतर संकटों का सामना कर रहा है तो सरकार को इसकी वास्तविक वजह जनता के सामने स्पष्ट करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मजबूत नेतृत्व और प्रगति के दावों के बीच बार-बार संकट की बात होना शासन व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है.

## सिक्स लेन के लिए हटेगी कब्र

एसडीएम के चेम्बर से निकला रास्ता

एमपीआरडीसी के साथ मुस्लिम लोग एम्बर आए

मौके पर ब्रिज निर्माण शुरू



प्रमोद व्यास उज्जैन. तारोफ-ए-काबिल है बेगमबाग का यह सब्र जनाब, शहर तरकी की खातिर कब्र पर चढ़ाया आखरी गुलाब... यह पंक्ति या इन दिनों सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत हरिफाटक के आगे बेगमबाग में चरितार्थ होते हुए दिखाई दीं. जिसमें मजबूत से ज्यादा आपसी समन्वय को लक्ष्यो दी गईं.

दरअसल 371.11 करोड़ रुपये की लागत से 6-लेन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हरीफाटक मार्ग पर शुरू हो गया है. यहां बेगमबाग में सघन बस्ती है, यहाँ न सिर्फ मकान हटाए गए बल्कि कब्र भी हटाई जा रही. उज्जैन विकास प्राधिकरण लगातार यहां पर मकान हटाने के कार्रवाई उस दशा में कर रहा है जब कानूनी बाधाएं समाप्त हो रही हैं और स्टे हट रहे.

कब्र पर भी सब्र -जुम्मे की नमाज के पहले गुरुवार को बेगमबाग क्षेत्र ने ऐसा उदाहरण

कलेक्टर ने बिताया सामंजस्य

उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की पहल पर मुस्लिम समाज, एमपीआरडीसी और प्रशासन के बीच हुई बैठकों के बाद एसडीएम एलएन गर्ग के चैंबर से ऐसा रास्ता निकला, जिसने विकास और धार्मिक आस्था के बीच संतुलन स्थापित कर दिया. मुस्लिम समाज के सहयोगात्मक रवैये के चलते अब मौके पर ब्रिज निर्माण का काम भी शुरू हो गया है. सामंजस्यो बड़ा राज् के साथ कुछ और सहयोगी आए, एमपीआरडीसी के अधिकारी दीपक मसी दस्तावेज लेकर पहुंचे थे, और बात बन गई.

मौके पर काम शुरू

उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने नवभारत से चर्चा में बताया कि महाकुंभ 2028 में 50 करोड़ श्रद्धालु आएंगे साधु संत आगों ऐसे में 30 हजार करोड़ के निर्माण कार्य विकास कार्य चल रहे हैं जितनी भी बाधा आ रही है उन्हें हटाया जा रहा है सबसे बड़ी बात यह है कि उज्जैन में जहां-जहां चौड़ीकरण हो रहा है मकान दुकान धार्मिक स्थल जद में आ रहे हैं कहां लोग सहयोग कर रहे हैं मुस्लिम समाज ने भी बेगमबाग की बस्ती के मकान अपने हाथों से हटाए हैं और धार्मिक स्थल भी हटाए जा रहे हैं, ऐसे में निर्माण मौके पर प्रारंभ हो गया है पुराने ब्रिज के मुहाने पर मशीन से बोर किया जा रहा है.

विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष

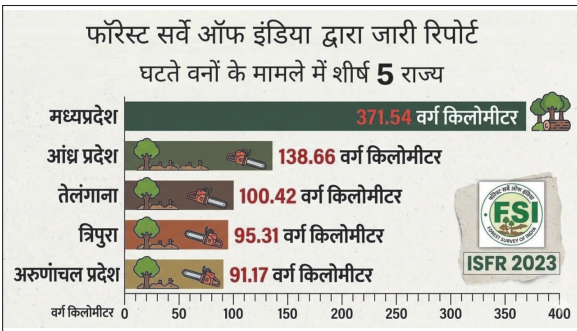
## देश में वन क्षेत्र में बढ़ोत्तरी, लेकिन मध्यप्रदेश को भारी नुकसान

मप्र में 346 वर्ग किलोमीटर का वन झाड़ियों में तब्दील

महाराष्ट्र में सबसे अधिक हरियाली, मप्र चौथे स्थान पर

साक्षी केसरवानी भोपाल, 04 जून. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देशभर में वृक्षों की हरियाली (ट्री कवर) के मामले में वृद्धि हुई है. नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 और 2023 के आंकड़ों के बीच देश के कुल 1 लाख 289.40 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी के साथ अब कुल ट्री कवर 1 लाख 12 हजार 14.34 वर्ग किलोमीटर हो गया है।

वहीं देश में वृक्षों की हरियाली के मामले में महाराष्ट्र कुल 1 हजार 524.88 वर्ग किलोमीटर के साथ देश में पहले पायदान पर है। तो राजस्थान 10 हजार 841.12 वर्ग किलोमीटर के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश 8 हजार 950.92 वर्ग किलोमीटर के साथ तीसरे स्थान पर है। जबकि मध्य प्रदेश इस मामले में 8 हजार 650.15 वर्ग किलोमीटर के साथ चौथे स्थान पर है। हालांकि 2021 के मुताबिक साल 2023 में सबसे अधिक सुधार वाले राज्यों में 702.75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ छत्तीसगढ़ शामिल है. वनों के घनत्व के मामले में अरुणाचल प्रदेश में 4 हजार



वन क्षेत्र में मप्र में कम हुई हरियाली

राष्ट्रीय स्तर पर देश में कुल वन क्षेत्र में 156.41 वर्ग किलोमीटर की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं मिजोरम, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक और केरल ऐसे प्रमुख राज्य हैं, जिन्होंने अपने वन क्षेत्र को वृद्धि की है. इसके ठीक उलट मप्र में सबसे अधिक 371.54 वर्ग किलोमीटर की कमी वन क्षेत्र में आई है। रिपोर्ट फॉरेस्ट एरिया के भीतर सबसे घने वनों के क्षरण में मप्र पूरे देश में शीर्ष पर पहुंच गया है। जहां कुल 4 हजार 855.48 वर्ग किलोमीटर का घना वन क्षेत्र अब पतले या खुले वनों में बदल चुका है। तो वहीं मप्र का करीब 346.44 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र अब केवल झाड़ियां बनकर रह गया है।

271.50 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में 3 हजार 4.04 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बड़ी गिरावट आई है।

वहीं झाड़ियों में तब्दील होने के मामले में आंध्र प्रदेश का 992.26 वर्ग किलोमीटर और ओडिशा का 651.77 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। पूरे देश की संयुक्त तस्वीर देखें तो कुल मिलाकर 40 हजार 709.28 वर्ग किलोमीटर का हरा-भरा घना क्षेत्र अब खुले वनों में बदल गया है जबकि 5 हजार 573.02 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र महज झाड़ियों में सिमट गया है।

बदलाव के कारण...

रिपोर्ट में वन क्षेत्र में हुई वृद्धि के लिए वनस्थितियों का प्राकृतिक विकास, विभिन्न वृक्षारोपण अभियानों, पारंपरिक वन क्षेत्रों में सुरक्षा के इंतजाम और जंगलों के बाहर वृक्षों के दायरे में हुई प्रगति को जिम्मेदार माना गया है। तो वनों के विनाश के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, झूम खेती का पुराना चलन, इसानी दखल व अतिक्रमण, तूफान, बाढ़ और भूखंडन, जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी कारण हैं।

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का नाम यथावत रखने की मांग

भोपाल, 4 जून . बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक विरोध तेज हो गया है. भाकपा ने इस प्रस्ताव को अनुचित बताते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है.

भाकपा मध्य प्रदेश के राज्य सचिव कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने कहा कि महान स्वाधीनता सेनानी एवं शिक्षाविद् बरकत उल्ला/बरकत उल्ला भोपाली का योदान स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है. उन्होंने कहा कि बरकतउल्ला भोपाली ने भारत की आजादी के लिए देश-विदेश में संघर्ष किया और वे निर्वासित सरकार में प्रमुख भूमिका से भी



जुड़े रहे. पार्टी ने कहा कि भोपाल की ऐतिहासिक पहचान और गौरव से जुड़े इस नाम को बदलने का प्रयास अस्वीकार्य है. इसे स्वतंत्रता सेनानी का अपमान बताया गया है. भाकपा ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि कार्य परिषद के इस प्रस्ताव को तत्काल अस्वीकार किया जाए और विश्वविद्यालय का नाम यथावत रखा जाए. साथ ही पार्टी ने अन्य राजनीतिक दलों से भी इस मुद्दे पर एकजुट होकर विरोध दर्ज कराने की अपील की है.

## हाई-प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग केस में जांच तेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार

7 आरोपी जेल में, डिजिटल सबूतों की जांच के बाद ही होगा बड़ा खुलासा

नव भारत न्यूज इंदौर . शहर के चर्चित हाई-प्रोफाइल हनीट्रेप और ब्लैकमेलिंग केस में फाइनेंस ब्रांच की जांच लगातार तेज होती जा रही है. मामले में गिरफ्तार किए गए सात आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि जल्द किए गए मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है. पुलिस का कहना है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ही पूरे नेटवर्क और

ब्लैकमेलिंग के दावों की सच्चाई सामने आएगी. इस मामले के तार एक संगठित सिंडिकेट से जुड़े होने की आशंका के चलते हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है. आरोपियों से बरामद मोबाइल फोन, लेपटॉप और अन्य डिजिटल डिवाइस को एफएसएफ भेजा गया है, जहां से रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट होगा कि आपस में किस तरह की बातचीत हुई और क्या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए आपत्तिजनक वीडियो तैयार किए गए थे. डीसीपी फाइनेंस ब्रांच राजेश त्रिपाठी ने बताया कि शोशल मीडिया पर 32 जैसी पेनड्राइव और वीडियो से जुड़े कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनके समर्थन में

कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिला है. उन्होंने साफ कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. जांच में पुलिस की नजर मुख्य आरोपी जैतन जैन पर भी टिकी हुई है. जिसके पुराने रिकॉर्ड और गतिविधियों को खंगाला जा रहा है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस मामले में आरोपी का संगठित खेल चलाया जा रहा था. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इस हाई प्रोफाइल मामले में बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है.

आयोजन पुलिस प्रशिक्षण शाला (पीटीएस) उज्जैन में नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण के पांचवें सत्र का दीक्षांत समारोह संपन्न

## प्रशिक्षण पूर्ण कर 206 नव आरक्षक पुलिस में हुए शामिल

विशेष संवाददाता भोपाल, 4 जून. मध्य प्रदेश पुलिस के प्रशिक्षण तंत्र की उत्कृष्ट परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पुलिस प्रशिक्षण शाला (पीटीएस) उज्जैन में नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण के पांचवें सत्र का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया. प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद 206 नव आरक्षक औपचारिक रूप से मध्य प्रदेश पुलिस बल में शामिल हो गए. समारोह में आयोजित पासिंग आउट परेड



उत्साह और गरिमामय वातावरण के बीच संपन्न हुई. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) रवि कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में संचालित किया

गया, जिसमें आधुनिक, व्यावहारिक और उच्च गुणवत्ता वाली पुलिसिंग दक्षताओं पर विशेष ध्यान दिया गया. परेड की सलामी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, उज्जैन जोन राकेश गुप्ता ने ली तथा नव आरक्षकों का निरीक्षण किया.

समारोह को संबोधित करते हुए राकेश गुप्ता ने कहा कि नव आरक्षक मध्य प्रदेश पुलिस की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. उन्होंने कहा कि वर्दी का वास्तविक सम्मान जनता के

पुलिस प्रशिक्षण शाला उज्जैन की पुलिस अधीक्षक मनीषा पाठक सेनी ने बताया कि प्रशिक्षुओं ने 313 दिवसीय कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया, जो दो सेमेस्टर्स में संचालित हुआ. प्रशिक्षण में 12 विषयों की लिखित परीक्षाएं, आउटडोर गतिविधियां, व्यावहारिक अभ्यास, अध्ययन भ्रमण, प्रदर्शन आधारित शिक्षण तथा आधुनिक हथियारों के साथ फायरिंग प्रशिक्षण शामिल था. तकनीक आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए साइबर वॉरियर योजना के अंतर्गत 61 प्रशिक्षुओं का चयन भी किया गया. समारोह के दौरान वार्षिक स्मारिका 'साहस' का विमोचन किया गया तथा नव आरक्षकों ने संविधान और पुलिस आचार संहिता के पालन की शपथ ली. उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया गया।

विश्वास से प्राप्त होता है और पुलिस कर्मियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान नागरिकों के

प्रति संवेदनशील एवं सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखना चाहिए.